

## एनएचआरसी 5 पूर्वोत्तरराज्योंमेंमानवाधिकारोंकेउल्लंघनपरकरेगाजनसुनवाई

<https://news.raftaar.in/national/nhrc-to-hold-public-hearings-on-human-rights-violations-in-5-northeastern-states>

इंफाल, 19 नवंबर (आईएनएस)। राष्ट्रीयमानवाधिकारआयोग (एनएचआरसी) पांचपूर्वोत्तरराज्योंअसम, अरुणाचलप्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुरऔरसिक्किममेंमानवाधिकारोंकेकथितउल्लंघनपरलोगोंकीशिकायतोंपरदिसंबरमेंएकजनसुनवाईकरेगा। इंफालमेंअधिकारियोंनेशुक्रवारकोकहाकिआयोग 15 और 16 दिसंबरकोदोदिवसीयजनसुनवाईकरेगाऔरइसकेरजिस्ट्रारनेलोगोंसे 20 नवंबरतकआयोगमेंअपनीशिकायतदर्जकरानेकोकहाहै। जनसुनवाईकेस्थानकेबारेमेंजल्दहीसूचितकियाजाएगा। दिल्लीकेएकवकीलआरिफजवादरद्वारादायरएकशिकायतपरकार्रवाईकरतेहुएएनएचआरसीनेहालहीमेंअसमकेपुलिसमहानिदेशकसेइससालमईसेराज्यमेंकथितफर्जीमुठभेड़ोंपरचारसप्ताहकेभीतरकार्रवाईरिपोर्टमांगीहै। मईकीशुरुआतसे 24 सेअधिकआरोपीमारेगएहैंऔरलगभग 40 अन्यघायलहोगए, यहउसवक्तहुअजबअभियुक्तोंनेकथिततौरपरहिरासतसेयाऑपरेशनकेदौरानभागनेकीकोशिशकीइसदौरानपुलिसनेउनपरगोलियांचलाई। वकीलजवादरनेपहलेएनएचआरसीमेंशिकायतदर्जकराईथी, जिसमेंआरोपलगायागयाथाकिपुलिसनेमुठभेड़ोंकेनामपरमईसेकईआरोपीव्यक्तियोंकोमारडाला। --

आईएनएसएचके/एएनएम

## प्रदूषणपरमानवाधिकारआयोगनेलियासंज्ञान:वाराणसीकेसोशलएक्टिविस्टने NHRC मेंकीथीशिकायत, रजिस्टर्डकियागयाकेस

<https://www.bhaskar.com/local/uttar-pradesh/varanasi/news/varanasis-social-activist-complained-to-nhrc-registered-case-129136386.html>

वाराणसीऔरउत्तरप्रदेशकेअन्यजिलोंमेंबढ़तेप्रदूषणकाराष्ट्रीयमानवाधिकारआयोग (NHRC) नेसंज्ञानलियाहै।पर्यावरणकेक्षेत्रमेंकामकरनेवालीसंस्थाक्रांतिफाउंडेशनकेअध्यक्षइंजीनियरराहुलकुमारसिंह कीशिकायतपरसंज्ञानलेतेहुएराष्ट्रीयमानवाधिकारआयोगनेकेसरजिस्टर्डकियाहै।आयोगजल्दहीइसशिकायत परसुनवाईकीतिथिनिर्धारितकरेगा।

प्रदेशकेसभीजिलोंमें AQI खराब

राहुलकुमारसिंहनेशनिवारकोदैनिकभास्करकोबतायाकिकाशीहीनहींबल्किउत्तरप्रदेशकेलगभगसभीजिलोंमें एअरकालिटीइंडेक्स (AQI) लगातारखराबचलरहाहै।कहीं-कहींतोयहआंकड़ा 400 केआसपासबनाहुआहैजोकिबेहदहीखराबहै।लगातारजहरीलीहवाकेकारणआमजनकोभारीपरेशानियोंकासामनाकरनापड़रहाहै।बच्चोंऔरबुजुर्गोंकीहालतसबसेज्यादाखराबहै।हालतयहहैकिघरसेबाहरनिकलतेहीलोगों कीआंखोंमेंजलनऔरसिरदर्दकीशिकायतआमबातहोगईहै।सड़कोंपरजामलगाहोनेपरलोगोंकोदमघुटनेजैसा एहसासहोताहै।अस्पतालोंमेंसांसलेनेमेंदिवक्त, आंखोंमेंजलनऔरअस्थमाकीशिकायतवालेरोगियोंकीसंख्यामेतेजीसेबढ़ोतरीहुईहै।

प्रदूषणकीइतनीखराबस्थितिकेबावजूदउत्तरप्रदेशसरकारइसविषयपरकोईठोसकार्रवाईनहींकररहीहै।उत्तर प्रदेशसरकारकेपासप्रदूषणकोकमकरनेकाकोईएक्शनप्लानभीनहींहै।प्रदेशसरकारनेआमजनताकोउनकेहालपरछोड़दियाहैऔरमौसमबदलनेकाइंतजारकररहीहै।

हरसालवहींस्थितिलेकिनकोईप्लाननहीं

राहुलकुमारसिंहनेकहाकिहरवर्षइसतरहकीस्थितिआनेकेबावजूदप्रदेशसरकारद्वाराकोईठोसप्लाननहींबनाया जाताहै।इसकेचलतेआमजनकोजहरीलीहवामेंसांसलेनेकेलिएमजबूरहोनापड़ताहै।उत्तरप्रदेशमेंनिर्माणकार्यों मेंप्रदूषणकोकमकरनेकेमानकोंकाबिल्कुलभीपालननहींहोरहाहै।इसकेअलावाधूलकोकमकरनेकेलिएपानी केछिड़कावजैसीछोटीव्यवस्थातककाइंतजामप्रदेशसरकारनहींकररहीहै।

प्रदेशसरकारकोतुरंतनिर्माणकार्योंमेंकटौतीऔरमानकोंकापालनसुनिश्चितकराना चाहिए।इसकेअलावाविद्यालयोंऔरकार्यालयोंकेकार्यदिवसोंमेंभीआवश्यककटौतीकरनी चाहिए।सड़कोंपरट्रैफिककोकमकरनेऔरजामन लगनेकीव्यवस्थासख्तीसेलागूकरनी चाहिए।इसकेअलावासड़कोंपरसमय-समयपरपानीकाछिड़कावभीसुनिश्चितकरनाहोगा, जिससेहवामेंउड़नेवालीधूलकीमात्राकोकमकियाजासके।

## **NHRC सेमिनारहॉलमेंपूर्व SC जजकोकाटनाथाफीता, परआखिरीपलोंमेंमहिलाहाउसकीपिंगस्टाफसेकरायागयाउद्घाटन**

<https://www.jansatta.com/national/housekeeping-staff-inaugurated-new-seminar-hall-in-nhrc-office-in-presence-of-former-sc-judge-arun-mishra/1926244/>

मानवाधिकार आयोगके अध्यक्ष व सुप्रीमकोर्टके सेवानिवृत्त जज अरुण मिश्रा की मौजूदगी में सेमिनार हॉल का उद्घाटन करने वाली विमलानेक हाकि उसनेक भी सोचा भी नहीं था कि वह अध्यक्ष और आयोगके अन्य सदस्यों के साथ मंच साझा करेगी।

मानवाधिकारों की रक्षा के लिए बने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नई दिल्ली स्थित कार्यालय में बने नए सेमिनार हॉल का फीता सुप्रीमकोर्टके पूर्व जज कोकाटनाथा। लेकिन आखिरी पलों में महिला हाउस की पिंगस्टाफ से इसका उद्घाटन कराया गया।

हमारे सहयोगी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में छ पे कॉलम दि ल्ली कॉन्फि डेंशियल कॉलम के मुताबिक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नई दिल्ली स्थित मानव अधिकार भवन कार्यालय में बने नए सेमिनार हॉल का उद्घाटन किया गया। इस सेमिनार हॉल का उद्घाटन मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सुप्रीमकोर्टके पूर्व जज अरुण मिश्रा को करना था। लेकिन आखिरी समय में मानवाधिकार आयोग कार्यालय में ही काम करने वाली हाउस की पिंगस्टाफ विमला से सेमिनार हॉल का उद्घाटन करवाया गया।

हाउस की पिंगस्टाफ से सेमिनार हॉल का उद्घाटन करवाए जाने को लेकर मानवाधिकार आयोग के अधिकारियों ने स माचार एजेंसी एन आई सेक हाकि कोरोना महामारी के दौरान सक्रिय भूमिका अदा करने वाले और आयोग के अंदर स मानता और गरिमा को बढ़ावा देने के मकसद से यह किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीते 16 नवंबर को आयोग में संविदा पर काम करने वाली हाउस की पिंगस्टाफ विमला और तीन अन्य कर्मचारियों से इसका उद्घाटन करवाया गया।

मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सुप्रीमकोर्टके सेवानिवृत्त जज अरुण मिश्रा की मौजूदगी में सेमिनार हॉल का उद्घाटन करने वाली विमलानेक हाकि उसनेक भी सोचा भी नहीं था कि वह अध्यक्ष और आयोगके अन्य सदस्यों के साथ मंच साझा करेगी। आयोग के कर्मचारियों ने भी सेमिनार हॉल का उद्घाटन हाउस की पिंगस्टाफ से करवाए जाने के अध्यक्ष के फैसले की सराहना की। इस दौरान जस्टिस मिश्रा ने कहा कि यह फैसला इस बात पर जोर देने के लिए लिया गया कि मानवाधिकार सभी के लिए है और यह लोगों के पद से प्रभावित नहीं होता है।

क्या है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। इसका मुख्य कार्य संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकारों की रक्षा करना है। जिसमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार जैसे कई अधिकार शामिल हैं। आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अलावा कई राज्यों में भी राज्य मानवाधिकार आयोग हैं।



## 5 पूर्वोत्तरराज्योंमेंमानवाधिकारोंकेउल्लंघनपरजनसुनवाईकरेगा NHRC

<https://www.newstracklive.com/news/nhrc-holds-public-hearing-on-human-rights-breaches-in-5-northeastern-states-sc1-nu318-ta915-1474169-1.html>

इंफाल: दिसंबरमें, राष्ट्रीयमानवाधिकारआयोग (एनएचआरसी) पांचपूर्वोत्तरराज्यों: असम, अरुणाचलप्रदेश, त्रिपुरा,

मणिपुर औरसिक्किममेंकथितमानवाधिकारोंकेउल्लंघनकेबारेमेंलोगोंकीशिकायतोंकोसुननेकेलिएएकजनसुनवाईबुलाएगा।इंफालमेंअधिकारियोंनेशुक्रवारकोकहाकिआयोग 15 और 16 दिसंबरकोदोदिवसीयजनसुनवाईआयोजितकरेगाऔररजिस्ट्रारनेनागरिकोंको 20 नवंबरतकअपनीशिकायतेंदर्जकरनेकेलिएआमंत्रितकियाहै।जनसुनवाईकेस्थानकीघोषणाशीघ्रहीकीजाएगी।

दिल्लीकेवकीलआरिफजवादरकीशिकायतकेआधारपरएनएचआरसीनेहालहीमेंअसमकेपुलिसमहानिदेशक सेइससालमईसेराज्यमेंसंदिग्ध "झूठीमुठभेड़ों" परकार्रवाईरिपोर्टकाअनुरोधकियाहै।मईकीशुरुआतसे, जबपुलिसनेउनपरगोलियांचलाईक्योंकि "आरोपियोंनेहिरासतसेयाऑपरेशनकेदौरानभागनेकीकोशिशकी, 24 सेअधिकलोगोंकीहत्याकरदीगईऔरलगभग 40 अन्यघायलहोगए।"

वकीलजवादरनेपहलेहीराष्ट्रीयमानवाधिकारआयोगकेपासएकशिकायतदर्जकराईथी, जिसमेंकहागयाथाकि "पुलिसनेमईकेबादसेमुठभेड़ोंकेनामपरकईआरोपीव्यक्तियोंकोमारडालाहै"।

## कार्रवाई न होने पर मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान

<https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/hamirpur/human-rights-commission-sought-clarification-in-the-case-of-death-hamirpur-news-knp6651458186>

राठ। जलालपुर थाने के बरहरा में आठ माह पूर्व युवक की संदिग्ध हालात में मौत मामले में कोर्ट के आदेश पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपियों पर कार्रवाई न होने पर मानवाधिकार आयोग ने निष्पक्ष जांच कर आख्या मांगी है।

बरहरा निवासी के शचंद्र ने बताया कि उनके भाई अखिलेश कुमार का गांव के मनप्यारे के यहां आना जाना था। अवैध संबंध के शक में मनप्यारे, जुगुल किशोर, उमाशंकर व संतोष उनके भाई से रंजितमान ले लगे। 11 मार्च की

शाम अखिलेश सरीलामें शिवरात्रि महोत्सव देखने गए थे।

15

मार्च को उनका शव सरीलामें पानी की टंकी के पास पड़ा मिला था। आरोप लगाया कि उक्त लोगों ने उनके भाई की हत्या की थी। पुलिस व डाक्टर को अपने

प्रभाव में लेकर मनमाफिक रिपोर्ट बनवा लीं। जिससे उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। मजबूरी में उन्होंने न्यायालय की शरण ली। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर 24 अगस्त को जरिया थाने में चारों के खिलाफ षडयंत्र चले

वह हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। उन्होंने मानवाधिकार आयोग से गुहार लगाई। पीठ के सदस्य ओपी दीक्षित ने मामले की विवेचना अपर पुलिस अधीक्षक से कराते हुए प्राथमिकता के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश एसपी

को दिए थे। शचंद्र ने बताया कि आयोग ने आठ नवंबर तक प्रगति आख्या मांगी थी। जिसके बावजूद अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है।

## वाराणसी: प्रदूषणपर राष्ट्रीयमानवाधिकारआयोगनेलियासंज्ञान, शिकायतपर दर्ज किया गया केस

<https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/varanasi/national-human-rights-commission-took-cognizance-on-pollution-case-registered-on-complaint-in-varanasi>

वाराणससमेत प्रदेशके दूसरे जिलोंमें बढ़ते प्रदूषण पर राष्ट्रीयमानवाधिकारआयोगने संज्ञान लिया है। पर्यावरण पर लगगातार कार्य करने वाली संस्था क्रांति फाउंडेशनके अध्यक्ष राहुल कुमार सिंह की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आयोगने मामला दर्ज किया है।

काशी तथा उत्तर प्रदेशके अन्य जिलोंमें बढ़ते प्रदूषण का राष्ट्रीयमानवाधिकारआयोगने संज्ञान लिया है। पर्यावरण पर लगगातार कार्य करने वाली संस्था क्रांति फाउंडेशनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ई० राहुल कुमार सिंह जी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीयमानवाधिकारआयोगने इस विषय पर केस दर्ज कर लिया है।

इस मामले पर शिकायतकर्ता ने बताया कि काशी हीनहीं बल्कि उत्तर प्रदेशके लगभग सभी जिलोंमें एअर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) लगातार खराब चल रहा है। कहीं-कहीं तो ये आंकड़ा चार सौ के आसपास बना हुआ है, जो कि बेहद खराब स्थिति में आता है।

प्रदेशके जिलोंमें लगातार जहरीली हवाके कारण आम जनताको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों और बुजुर्गोंकी हालत सबसे ज्यादा खराब है। हालात ये हैं कि घर से बाहर निकलते ही लोगोंकी आंखोंमें जलन और सिर दर्द की शिकायत आम बात होगई है।

सड़कों पर चलने वाले राहगीरोंकी स्थिति सबसे खराब है। सड़कों पर जामकी स्थिति होने पर लोगोंको दमघुटने जैसा अहसास होने लगा है। अस्पतालोंमें सांसमे दिक्कत, आंखोंमें जलन, अस्थमा इत्यादिकी शिकायत करने वाले रोगियोंकी संख्यामें बढ़ोतरी हुई है।

प्रदेशमें प्रदूषणकी खराब स्थिति के बावजूद सरकार इस विषय पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकारके पास प्रदूषणको कम करने का कोई एक्शन प्लान नहीं है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकारको तुरंत निर्माण कार्योंमें कटौती और मानकों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अलावा विद्यालयों, कार्यालयोंके कार्य दिवसोंमें भी आवश्यक कटौती करनी चाहिए। सड़कों पर ट्रैफिकको कम करने और जाम न लगने की व्यवस्था सख्ती से लागू करनी चाहिए।

## वाराणसीके सोशलएक्टिविस्टने प्रदूषणपर मानवाधिकार आयोगने लिया संज्ञान

<https://tarunmitra.in/human-rights-commission-took-cognizance-of-pollution-by-social-activist-of-varanasi/484547>

वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में बढ़ते प्रदूषण का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने संज्ञान लिया है। पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था क्रांति फाउंडेशन के अध्यक्ष इंजीनियर राहुल कुमार सिंह की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केसर जिस्टर्ड किया है। आयोग जल्द ही इस शिकायत पर सुनवाई की तिथि निर्धारित करेगा।

उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में एअर कालिटी इंडेक्स (AQI) लगातार खराब चल रहा है। कहीं-कहीं तो यह आंकड़ा 400

के आसपास बना हुआ है जो कि बेहद ही खराब है। लगातार जहरीली हवा के कारण आम जन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों और बुजुर्गों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। हालत यह है कि घर से बाहर निकलते ही लोगों की आंखों में जलन और सिर दर्द की शिकायत आम बात हो गई है। सड़कों पर जाम लगा होने पर लोगों को दमघुटने जैसा एहसास होता है। अस्पतालों में सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और अस्थमा की शिकायत वाले रोगियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।

प्रदूषण की इतनी खराब स्थिति के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार इस विषय पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के पास प्रदूषण को कम करने का कोई एक्शन प्लान भी नहीं है। प्रदेश सरकार ने आम जनता को उनके हल पर छोड़ दिया है और मौसम बदलने का इंतजार कर रही है।



## **Babul Supriyo accuses 'BJP mob' of pelting stones at him in Tripura, calls it party of backstabbers**

<https://www.indiatoday.in/india/story/tripura-agartala-tmc-babul-supriyo-bjp-mob-pelted-stones-1879048-2021-11-20>

Babul Supriyo took to Twitter to allege that a 'mob' of BJP workers pelted stones at him in Tripura's capital city on Saturday.

Trinamool Congress's new recruit Babul Supriyo today accused a "violent BJP mob" of pelting stones at him in Tripura capital Agartala and alleged that the party resorts to "filth in Tripura".

Supriyo's attack on his former party comes amid peaking political tension in the northeastern state over the past several weeks. Supriyo added that the "cowards" fled when he tried to confront the alleged attackers.

"Faced a violent mob of @BJP4India in #Agartala, abusing & Pelting Stones at me got down frm the car to confront them & cowards fled?? It's a joke/shame that BJP preaches against Political Violence given the filth I see them resort to in Tripura," the 50-year-old former BJP MP tweeted tagging Trinamool and party colleague Abhishek Banerjee.

He added another tweet calling the BJP a 'party of backstabbers' and also put up an apparent challenge: "Let me see how you win Asansol back". Supriyo won Bengal's Asansol twice on a BJP ticket.

His second tweet - a pat on his own back - was about his victories in Asansol and also about having a 'spine' to leave the MP seat midway.

The Trinamool Congress is taking on the Biplab Deb-led BJP government in Tripura to get a foothold in the state ahead of the 2023 Assembly polls which has led to several clashes and war of words.

Bengal Chief Minister Mamata Banerjee's nephew and MP Abhishek Banerjee's rallies too were cancelled and postponed several times as the BJP put up a fierce opposition against the party's attempts to make inroads in the state that has seen a long Left-dominated rule in the past.

**Recent reports of communal violence in the state led to a crackdown on several journalists and social media posts that the Tripura police called "provocative posts". Several reports of violence led to the National Human Rights Commission seeking an action taken report from the state government within four weeks on complaints of political and religious violence.**



RTI activist Saket Gokhale, who joined the TMC recently, had filed the complaint and mentioned the attack on the party's Rajya Sabha MP Sushmita Dev during a campaign rally in October.

TMC has on several occasions accused the ruling party of trying to stop their rallies, attacking them and vandalising their vehicles. The party even went to the Supreme Court with a plea to look into the matter. The BJP has denied the allegations accusing the TMC of violence and claimed it was a "conspiracy" of outsiders to malign the state government with "fake news."

Babul Supriyo, who switched to the BJP last month in a surprise move, was a fierce critic of the Mamata Banerjee government in Bengal before he quit the BJP. He had announced he was quitting politics soon after he was asked to step down as a junior minister in the Environment Ministry in this year's key Cabinet reshuffle.

### **Thane: Con couple held for cheating ration shop owner in Bhayandar**

<https://www.freepressjournal.in/mumbai/thane-con-couple-held-for-cheating-ration-shop-owner-in-bhayandar>

The con-couple impersonated as government officers attached to the National Human Rights Body to execute their nefarious activities.

As the second part of the Bollywood blockbuster movie- "Bunty Aur Babli" hit the silver screens on Friday, a real-life version of the reel con-couple was arrested by the Mira Bhayandar-Vasai Virar (MBVV) police for cheating a ration shop owner in Bhayandar (east).

The con-couple impersonated as government officers attached to the National Human Rights Body to execute their nefarious activities.

As the second part of the Bollywood blockbuster movie- "Bunty Aur Babli" hit the silver screens on Friday, a real-life version of the reel con-couple was arrested by the Mira Bhayandar-Vasai Virar (MBVV) police for cheating a ration shop owner in Bhayandar (east).

The con-couple impersonated as government officers attached to the National Human Rights Body to execute their nefarious activities.

In his complaint to the police, the couple who identified themselves as Shabana Bano Balubhai Siddique (30) and her accomplice Prashant Ganga Vishnu (27) barged into his authorized fair price shop (FPS). They flashed identity cards and asked the shop owner to produce complaint books and other documents related to the public distribution of food grains and other commodities.

The accused demanded Rs. 50,000 to evade action. The shopkeeper handed over Rs. 20,000 with a promise of paying the remaining amount next week.

However, he mustered courage and registered a complaint with the Navghar police. A team led by Senior Police Inspector- Milind Desai under the supervision of Additional Commissioner-S. Jaykumar and DCP- Amit Kale (Zone I) investigated the matter and apprehended the duo who were found to be in possession of bogus identity cards and scores of letter-pads of the New Delhi-based human rights and social justice commission.

Apart from this, the recovery of a list of local fair price shops in the twin-city indicates their involvement or plan to dupe and similarly threaten other shop owners said the police.

While Siddique is a resident of Santacruz in Mumbai, her accomplice stays in Mira Road. An offence under sections 384 (extortion), 419 (cheating by personation) and 170 (impersonating a public servant) of the Indian Penal Code have been registered against the accused who have been remanded to custody. Further investigations were underway.



### **NHRC to hold hearing on rights violations in 5 NE states**

<https://www.sentinelassam.com/topheadlines/nhrc-to-hold-hearing-on-rights-violations-in-5-ne-states-563889>

The National Human Rights Commission (NHRC) would hold a public hearing in December on grievances of the people on the alleged violation of human rights in five northeastern states – Assam, Arunachal Pradesh, Tripura, Manipur and Sikkim.

IMPHAL: The National Human Rights Commission (NHRC) would hold a public hearing in December on grievances of the people on the alleged violation of human rights in five northeastern states – Assam, Arunachal Pradesh, Tripura, Manipur and Sikkim.

Officials in Imphal said on Friday that the Commission would hold a two-day public hearing on December 15 and 16, and its Registrar asked the people to file their complaint to the commission by November 20.

The venue of the public hearing would be notified soon.

Acting on a complaint filed by a Delhi-based lawyer Arif Jwadder, the NHRC has recently sought Action Taken Reports, within four weeks, from Assam's Director General of Police on alleged "fake encounters" in the state since May this year.

More than 24 accused have been killed and around 40 others injured since early May when police fired on them as the "accused allegedly tried to escape from custody or during operations".

Lawyer Jwadder had earlier lodged a complaint to the NHRC, alleging "police killed many accused persons since May in the name of encounters". (IANS)

### **Exam burden issue reaches NHRC, Child panel**

<https://www.nationalheraldindia.com/national/exam-burden-issue-reaches-nhrc-child-panel>

After Delhi govt's decision not to hold an examination for students from Class 3 to 8 studying in its schools, parents of children studying in private schools are feeling discriminated

After the Delhi government's decision not to hold an examination for the students from Class 3 to 8 studying in its schools, parents of the children studying in the private schools are feeling discriminated as the rule does not apply for the private schools.

Parents are calling it discriminatory and Online exams are also being sought for Class 9 and 11. The controversy related to the examination has now reached to institutions like the National Human Rights Commission and the National Commission for Protection of Child Rights.

According to the Directorate of Education, Government of Delhi, students studying in classes 3 to 8 will not have to take the annual examinations. The directorate said that this decision will be applicable to government and government-aided schools. This decision of the Delhi government is not acceptable to the millions of parents whose children study in private schools.

Parents have alleged discrimination, saying that whether government or private, all schools are closed for children studying in small classes for almost a year.

President of Delhi Parents Association Aparajita Gautam said, "We have written a letter to the Governor and the Chief Minister. We have raised the issue that the education department has addressed the concern of student studying in government school while children of private schools have been ignored."

Gautam said, "Till now we were appealing for online exams of 9th and 11th class. The Education Department did not respond to our appeal. From above, the department issued orders only for the children of 8th class in the government schools.

"Now, by writing a letter to the Governor, Chief Minister, NHRC and National Commission for Protection of Child Rights, an appeal has been made to conduct online exams of Class 9th and 11th in private schools of Delhi."

At the same time, President of All India Parents Association, Ashok Aggarwal said, "We welcome the decision of the Delhi government but it needs further improvement. In addition to the students up to the eighth standard, the government should adopt the same policy for the students of class 9th and 11th. Due to Corona, all the students of

Delhi who are studying in small classes are not able to go to school. In this case, this rule should be applied to private school students also."

In favour of the decision taken by the Delhi government, educationist K.C. Kandpal said, "Due to the lockdown, many government school students have also been deprived of online education due to lack of resources. However, students studying in private schools have also been affected. In such a situation, if the government wants, students studying in private schools can also be given relief.

According to Vaibhavi, a student of Class 11, studying in a private school in Delhi, said, "There is no regular education in schools. We have studied online for the whole year. In such a situation, examinations could also be conducted online, but this decision has not been implemented. Now the offline examination has also been announced from next week."



## **Govt reluctance to resolve rights abuse issues weakens NHRC**

<https://www.newagebd.net/article/155225/govt-reluctance-to-resolve-rights-abuse-issues-weakens-nhrc>

AN APPARENT unwillingness of the home ministry to hold meetings with the National Human Rights Commission, taking the law enforcement agencies on board, on dozens of complaints of rights violation and abuse that have been pending for years without reasonable explanations is worrying.

This is so mainly because the unwillingness that the government shows delays an early disposal of the rights violation issues while this keeps adding to the impunity of a sort that may further encourage the commission of the violations in the absence of effective checks. While this also suggests a tendency of the authorities involved to keep the issues unresolved, this at the same time weakens the commission as an institution of accountability.

The commission is reported to have approached the home ministry over telephone multiple times and written to the ministry at least twice this year, the first time early this year and the second time in August, seeking to hold the joint meeting on pending complaints against the law enforcement agencies and other issues, including violence against women and girl children and trafficking in humans. While the commission is reported to have been left with no response from the home ministry, the home minister seeks to plead ignorance about any such letter and to say that the secretary concerned might have the answer if there were any such letters.

The commission chair is also reported to have spoken to the home minister at a programme of the Rapid Action Battalion in Dhaka on September 23 about the need for the meeting, but the commission is yet to receive any response.

The commission has compiled lists of 91 allegations against the law enforcement agencies lodged since 2012. Of the complaints, 20 are related to enforced disappearances, 11 to 'crossfire' death, 15 to custodial death, 19 to incidents of torture and 26 to domestic violence, the filing of false cases and other forms of rights abuse. The commission says that the government authorities have sent letters to the police chief on 52 of the 91 complaints and it has received copies of the letters. But the commission is unaware of any response from the office of the police chief. What has happened regarding the willingness of the commission to hold the meetings with the government authorities on allegations of rights abuse against the law enforcement agencies and an apparent unwillingness of the government authorities to either respond to the commission requests or hold the meeting suggests that the resolution of the issues would further lie over unless the government becomes sincere about resolution

of the rights abuse complaints that could strengthen the commission and better the image of the government both at home and abroad.

The government's unwillingness to resolve issues of rights abuse by the law enforcement agencies despite repeated requests by the Human Rights Commission does not only weaken the commission as an institution of accountability, but this also erodes people's confidence in the commission, delays the disposal of allegations creating the scope for further abuse of rights and earns the government a bad name at home and abroad. The government must attend to all these issues early and in earnest.